जाते हैं, मात्रा के आधार पर नहीं। व्यक्तिगत लाइसेंसों के उपयोग की सीमा के बारे में भी आंकड़े नहीं रखे जाते।

विवरण

(क) अप्रैल, 1977 से जून, 1977 के दौरान आयात किये गये खाद्य तेलों की मात्रा दर्शाने वाला विवरण।

खाद्य तेल	मात्रा
	(हजार कि ग्रा०)
ताड़ का तेल	40113
नारियल का तेल	956
सोयाबीन का तेल	72208
रेपसीड का तेल	64618
मूंगफली का तेल	491
योग	178386

(ख) अप्रैल, 77 से जून 77 के दौरान आयात किये गये खाद्य तेलों के औसत एकक मूल्य दर्शाने वाला विवरण।

खाद्य तेल	औसत एकक मूल्य (लागत बीमा भाड़ा आधार) रु० प्रति किग्रा०
ताड़ का तेल	5.27
नारियल का तेल	6.48
सोयाबीन का तेल	5.11
रेपसीड का तेल	5.49
मूंगफली का तेल	7.99

टिप्पणी: आंकड़े अनन्तिम हैं तथा उनमें संशोधन हो सकता है।

जयगढ़ और मोती डूंगरी, जयपुर में मिला खजाना

3292. **श्री रामनरेश कुशवाहा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जयपुर में जयगढ़ और मोती डूंगरी आदि में मिले खजाने को जमा न कराने अथवा कम मात्रा में जमा कराने के कारण क्या हैं;

(ख) बाकी खजाना किस स्थान पर रखा गया है;

(ग) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्ति कौन-कौन से हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) से (घ). "छिपाये गये खजाने" का पता लगाने के लिए केवल जयगढ़ किले में ही खुदाई की गई थी। यह कार्य 1976 में जून से नवम्बर तक की अवधि में किया गया था। उक्त खुदाई में कोई खजाना नहीं मिला।

Crisis of Mustard Oil in Orissa and West Bengal

3293. SHRI SIVAJI PATNAIK: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the fact that the serious crisis of mustard oil in Orissa and West Bengal has deepened following the issue of price control order; and

(b) if so, the steps Government propose to take in solving the problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL): (a) There have

been reports that mustard oil was not available at a retail price not exceeding Rs. 10 per kg. the limit fixed in the Mustard Oil (Price Control) Order, 1977 dated 30-9-77, when its validity was being challenged in the Supreme Court.

(b) State Governments have been advised to take stern action against those who offend the provisions of the Essential Commodities Act. Arrangements have been made to meet the demand of refined rapeseed oil, as substitute oil, as may be required by the State Governments at the end retail price of Rs. 7.50 per kg.

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना

3294. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :**
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो शाखायें खोलने के लिए स्थान का चुनाव करने सम्बन्धी मापदंड क्या है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में कितनी शाखायें खोली जानी हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाओं का जाल बिछाने की सलाह दी गई है। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में चार कार्यालय खोलने पर ही वे महानगरीय केन्द्र में एक और तथा पहले से बैंक शाखा वाले स्थान पर एक और शाखा के हिसाब से दो नयी शाखाएं खोलने के हकदार होंगे।

ग्रामीण विकास की और क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने की आवश्यकता की दृष्टि से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के शाखा विस्तार के वर्तमान तरीके का अनुमान लगाने और आने वाले समय में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति की नियुक्ति की है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) शाखाएं खोलने के लिए स्थानों का चुनाव करने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने, बैंकों को सलाह दी है बैंक रहित क्षेत्रों, बैंक रहित खंड मुख्यालयों और उन बैंकों रहित जिला मुख्यालयों में जहां ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं की जनसंख्या व्याप्ति अपेक्षया कम है, शाखाएं खोलने की प्राथमिकता दी जाये। इन प्राथमिकताओं के भीतर बैंक अपनी शाखाओं का स्थान निर्धारित करने में पहले आधार मूल सुविधाओं, विकास क्षमता, विशेष रूप से आस पास के क्षेत्रों आदि में कृषि कार्य के लिए ऋण–क्षमता आदि की उपलब्धता का अनुमान लगाते हैं।

(ग) बैंकों द्वारा तीन वर्षीय रोलिंग योजना के आधार पर शाखा विस्तार का कार्य किया जा रहा है। पक्की (फर्म) योजना केवल पहले वर्ष के लिए उपलब्ध होती है। 1978 के लिए पक्की योजना अभी उपलब्ध होनी है। लेकिन, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट दी है कि सितम्बर, 1977 के अन्त तक 2333 ग्रामीण कार्यालयों को खोलने के लिए लाइसेंस/आबंटन बैंकों के पास बकाया थे।